(b) For recruitment to posts under the Central Government, the upper age limit generally varies from 24 to 30 for direct recruitment to different posts. In the nationalised banks, the upper age limit for clerks varies from 25 to 28 while for staff in other lower categories, it varies from 23 to 45.

(c) and (d). It is not possible to make any change in the existing age limits, as age limits for recruitment to Central Services/posts are prescribed from time to time keeping in view the various relevant factors and specially having regard to the qualifications and experience required for that service/post. The basic objective is to ensure that Government is able to secure the services of persons at an age most suited for the service/post concerned.

कोयले का अवैध खनन

4746. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोकिंग कोल का अवैध रूप से खनन किया जाता है तथा इसे बाजार में बेचा जाता है जिससे देश के इस्पात कारखानों को कठिनाई होती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गैर कानूनी खनन कार्य बन्द हो गया है किन्तु संभव है कि गैर कानूनी खनन कार्य के कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो प्राधिकारियों की जानकारी में न आए हों । परन्तु इस वजह से इस्पात कारखानों को कोई कठिनाई नहीं हुई है ।

उद्योगों को बिजली की सप्लाई

4747. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण, 1977–78 में यह बताया गया है कि बिजली की कमी के कारण 1977–78 में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई और यदि हां, तो बिजली की कमी वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) घरेलू कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की फिजूल खर्ची रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने अर्थ व्यवस्था और उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां । कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी के कारणों में से एक कारण बिजली की कमी होना बताया गया है । इस समय निम्नलिखित राज्यों में बिजली पर कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू है :—

1. उत्तर प्रदेश
2. राजस्थान
3. जम्मू व काश्मीर
4. दिल्ली
5. महाराष्ट्र
6. मध्य प्रदेश
7. कर्नाटक
8. पश्चिम बंगाल
9. असम
10. गोआ

(ख) घरेलू उपभोक्ता सामान्यतया आवश्यकता पड़ने पर बिजली इस्तेमाल करते हैं । बिजली की कमी वाले राज्यों में बिजली की फजूलखर्ची और दिखावटी प्रयोजनों हेतु बिजली के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिये राज्य बिजली बोर्ड ने सामान्य अनुदेश तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । बिजली की गम्भीर कमी महसूस करने वाले कुछ राज्यों में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा वातानुकूलन, नोअन

लाइटों, इत्यादि जैसे कुछ कार्यों के लिए बिजली का उपयोग किए जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(ग) अर्थ व्यवस्था और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार के उपाय करती आ रही है । अल्पकालीन कार्यक्रम में मुख्यतया वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने में शीघ्रता लाने पर बल दिया जा रहा है । दीर्घकालीन कार्यक्रम में सरकार का विचार 1978—83 की पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में 18500 मेगावाट की वृद्धि करने का है ।

Resolutions passed by M.C.D.

4748. CHAUDHURY BRAHM PERKASH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received certain resolutions passed by the Municipal Corporation of Delhi for approval;

(b) whether he has received certain letters from the Chairman, Standing Committee of the Municipal Corporation of Delhi in this regard;

(c) if so, the particulars of (a) and (b) above;

(d) whether Government have since accorded their sanction to the said proposals;

(e) if so, when; and

(f) if not, the reasons advanced to the M.C.D. for not accepting their proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (f). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Curtailment of Annual Plan allocation for Tripura

4749. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the wide-spread resentment among the people of Tripura over the curtailment of State Government's demand for plan allocation from Rs. 32.30 crores to Rs. 22.70 crores;

(b) if so, the reason for curtailment; and

(c) whether Government do not consider that special attention is necessary to develop backward States like Tripura?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). No, Sir. The Annual Plan for 1978-79 for Tripura was finalised at Rs. 22.270 crores by the Planning Commission in discussion with the Chief Minister. The outlay for 1978-79 marks a step up of 43.8% over the approved outlay for 1977-78. The State's own net resources for 1978-79 are negative, i.e. minus Rs. 5.87 crores.

(c) In recognition of the special problems of Tripura and its backwardness, Government have already provided for a specially liberal scheme of Central Assistance under which the gap between the resources of the State and its Plan is met by the Central Government by way of assistance. In addition, Tripura as a constituent unit of the North East Council, benefits from the projects/schemes of regional importance undertaken by the North East Council.

Change in development strategy of plan

4750. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to change the developmental strategy of the plan;

(b) if so, what are the new targets for growth rate; and

(c) whether bigger industries would be kept in abeyance for the plan period?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) In the draft Five Year Plan 1978-83, a new developmental strategy is proposed with a view